foreign exchange earning of individuals other than trade and business are not separately available with the RBI. However, the total current earnings/receipts of foreign exchange during the last three years are as under:—

1995-96	US$ 49,636 mn
1996-97	US$ 55,240 mn
1997-98	US$ 57,538 mn

अहमदाबाद और राजकोट स्थित केन्द्रीय सीमा और उत्पाद शुल्क कार्यालय में छापे

200. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केन्द्रीय जांच ब्यूरो और विभागीय सतर्कता कार्यालय द्वारा अहमदाबाद और राजकोट स्थित केन्द्रीय सीमा और उत्पाद शुल्क विभाग में कोई छापा मारा गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार और गबन में लिप्त पाए गए और गिरफ्तार किए गए तथा उनके पास कुल कितनी धनराशि बरामद की गई;

(ग) क्या उक्त कार्यालयों में बड़ी तादाद में अनियमितता और गबन के मामले प्रकाश में आए हैं; और

(घ) कितने अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी किए गए हैं अथवा विचाराधीन हैं?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन): (क) 1996, 1997 और 1998 के दौरान अहमदाबाद और राजकोट स्थित केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क आयुक्तालय के कार्यालयों में कोई छापे नहीं मारे गए थे। तथापि, उक्त अवधि के दौरान उक्त कार्यालयों के 7 अधिकारियों के आवासीय परिसरों में तलाशियां ली गई थीं।

(ख) और (ग) सात अधिकारी भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं में शामिल पाए गए थे। पकड़े गए चार मामलों में, अधिकारियों से 6500/-रुपये वसूल किए गए थे जिन्होंने इसे अवैध पारितोषिक के रूप में लेना स्वीकार किया था। एक मामले में, शेयरों और ऋणपत्रों में 4.06 लाख रुपये और बैंकों में 5.76 लाख रुपये के निवेश को उद्घाटित करने वाले दस्तावेज बरामद किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 18,900/-रुपये के मूल्य का अवैध रूप से आयातित माल भी बरामद किया गया था। इस मामले में, पार्टी ने अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 33.12 लाख रुपये की रकम की प्रतिअदायगी का दावा करने का प्रयास किया था। एक दूसरे मामले में, उसी कर्मचारी के पास 13.87 लाख रुपये के मूल्य की असमानुपाती परिसंपत्तियां पाई गई थी। इन अधिकारियों को तकनीकी रूप से हिरासत में लिया गया था।

(घ) उपर्युक्त मामलों में उन अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या शून्य है जिनकी सेवाएं समाप्त करने के संबंध में आदेश पारित कर दिए गए हैं अथवा वे विचाराधीन हैं।

भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन

201. **श्री डी० पी० यादव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय मुद्रा के लगातार अवमूल्यन के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार रुपए के अवमूल्यन को रोकने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) अप्रैल—अगस्त, 1998 के दौरान पूर्व एशियाई वित्तीय बाजारों में व्याप्त हलचल के प्रतिकूल माहौल और उससे उपजी बदहवासी और देश में घट रहे घटनाक्रम से संबंधित अनिश्चितताओं के कारण भारतीय रुपया अधोगामी दबाव में रहा। सितम्बर, 1998 से विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता बहाल हुई है।

(ख) रुपए की विनिमय दर बाजार द्वारा निर्धारित होती है। विनिमय दर के उतार-चढ़ाव का सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बारीकी से अनुवीक्षण किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक जहां विनिमय दर के निरूपण जैसे कि विदेशी प्रतिस्पर्द्धात्मकता का संरक्षण करने एवं उसमें सुधार करने में बाजार के घटनाक्रम के परिलक्षित होने की अनुमति देता है, वहीं जब भी आवश्यक हो विदेशी विनिमय बाजारों में हस्तक्षेप करता है और रुपए पर अनिश्चित दबावों को कारगर ढंग से रोकने तथा विदेशी मुद्रा बाजार की सुव्यवस्थित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त मौद्रिक एवं अन्य उपाय लागू करता है। भुगतान संतुलन में उतार-चढ़ाव की नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है और नीति संबंधी उपाय किए जाते हैं ताकि चालू खाता घाटे के स्तर को

वहनीय स्तरों के भीतर रखा जा सके तथा इसके साथ ही देश की विदेशी वित्त सहायता की आवश्यकता और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडारों के पर्याप्त स्तर के अनुरूप पूंजी प्रवाह को विनियमित किया जा सके।

Erosion in Value of UTI's Premier Scheme

202. SHRI GAYA SINGH:
SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the recent erosion in value of UTI's Premier Scheme US-64;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Central Trade Unions have expressed concern over this erosion as a large percentage of social security funds were invested in the scheme; and

(d) if so, the details in this regard and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) and (b) According to Unit Trust of India (UTI), due to unfavourable stock market conditions there was a notionals depreciation in value of US-64 investment or Rs. 3566 crores as on 30th June, 1998.

(c) and (d) US-64 units are not a part of approved list of investment for provident/pension funds.

Remittance of Royalties by Nestle India Limited

203. SHRI KULDIP NAYYAR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Nestle India Limited remitted Rs. 43 crores in 1997 and Rs. 35 crores in 1996 on account of royalties;

(b) what is the basis on which the royalties payable are calculated;

(c) the manner in which Government check its validity;

(d) what is the justification of such large sums of money being sent out of the country by a consumer goods manufacturer; and

(e) whether the payment of royalty tax is deductable; if so, what is the loss on tax revenue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) Yes Sir.

(b) Royalty is paid at 5% of turnover, net of excise duty on domestic sales. For export sales, the royalty is paid at 7%.

(c) The payment of royalty is governed as per the Agreement which is duly approved by the Reserve Bank of India.

(d) Royalty is paid for providing technical assistance as per the Agreement.

(e) Payment of royalty is an allowable expenditure as per the provisions of Income-tax Act, 1961 for computing taxable income. However, 20% of gross royalty remitted abroad is deducted as tax at source. Royalty tax is not deductible in the computation of income or from the final tax payable by Nestle India.

US 64 Crisis in UTI

204. SHRI P. PRABHAKAR REDDY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the UTI was recently in the grip of a serious redemption pressure of US 64 units;

(b) if so, the number of units offered for repurchase and the number actually purchased by the UTI as on date;

(c) by when the backlog; if any, is likely to be cleared; and

(d) the steps taken to generate public confidence in the credibility of the UTI?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) to (c)